IAS GS World PCS

Committed To Excellence

Prelims Capsule

प्रमुख अंग्रेजी अखबारों से...

Corp. Office:-
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph.:- 011-27658013, 7042772062/63

चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड

टाइम्स ऑफ इंडिया/इकॉनमिक
(26 सितम्बर)

संदर्भ–

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, 'चौंपियंस ऑफ द अर्थ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भारत के साथ-साथ फ्रांस को भी इस पुरस्कार के लिए इसलिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि दोनों ही देशों ने समान प्रयासों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की है।

क्यों दिया गया पुरस्कार?

- इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर अग्रणी एवं उत्साही कार्यों के लिए और पर्यावरणीय कार्यों में सहयोग के नये क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 'नीति नेतृत्व' श्रेणी के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- प्रधानमंत्री को 2022 तक भारत में प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने का संकल्प लेने और मैक्रों को पर्यावरण के लिए वैश्विक समझौते को लेकर सराहना की गयी।
- दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने पूरे विश्व में इस बारे में जाग्रति फैलाई तथा अन्य देशों को भी सौर गठबंधन में शामिल करने हेतु सफलतापूर्वक प्रोत्साहित किया।

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड–

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2005 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से उत्कृष्ट पर्यावरण हितैषी कार्य करने वाले व्यक्तियों को पहचानने के लिए वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम के रूप में 'चैंपियंस ऑफ अर्थ' पुरस्कार की स्थापना की।
- आम तौर पर प्रतिवर्ष पांच से सात विजेताओं का चयन किया जाता है।
- प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए एक पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया जाता है। विजेता पुरस्कार प्राप्ति हेतु भाषण देते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं।
- वर्ष 2017 में 'यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ' श्रेणी की भी शुरुआत की गई।
- इसके अंतर्गत 18 से 30 वर्ष के उन व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक एवं उत्कृष्ट पहल की हो।

अन्य मुख्य बिंदु–

- केरल के कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ते हुए उद्यमी दृष्टि दिखाने के लिए अवॉर्ड दिया गया है।
- कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व को यह सन्देश देता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी वैश्विक विकास में अग्रणी भूमिका निभाई जा सकती है।
- कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 'नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में नेतृत्व' के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

GS World Committed To Excellence

कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को मिली अनुमति

फाइनेंसियल एक्सप्रेस/टाइम्स ऑफ इंडिया/लाइव मिंट

संदर्भ-

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी करते हुए देश भर की अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) की अनुमति दे दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधा प्रसारण सेवा की शुरुआत वह अपने यहां से करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया।
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनहित में जारी है, और इससे पारदर्शिता आएगी।

क्या कहा कोर्ट ने?

- कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जिससे न्यायिक व्यवस्था की जवाबदेही बढ़ेगी।
- हालांकि, कोर्ट ने अयोध्या और आरक्षण जैसे मुद्दों को संवेदनशील बताते हुए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह कोर्ट की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के लिए नियम बनाएगी।
- न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत लाइव स्ट्रीमिंग के नियम-कानून बनाए जाएं।
- सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल इसे प्रायोगिक तौर पर ही लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि-

- सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था।
- शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट से शुरू किया जाएगा, पर इसके लिए कुछ नियमों का पालन किया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने महत्त्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके सीधे प्रसारण को लेकर केंद्र से जवाब मांगा था।

भारत का पहला कोयला-गैसीफिकेशन उर्वरक प्लांट

लाइव मिंट/इकनोमिक टाइम्स/बिजनेस लाइन/हिंदुस्तान टाइम्स (22 सितम्बर)

संदर्भ-

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने ओडिशा के तलचर में देश के पहले कोयला-गैसीफिकेशन उर्वरक प्लांट के कार्य को लांच किया।
- इस उर्वरक प्लांट का निर्माण तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
- तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में GAIL का हिस्सा, 29.67%, कोल इंडिया लिमिटेड का हिस्सा 29.67%, राष्ट्रीय केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का हिस्सा 29.67% तथा भारतीय उर्वरक कारपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा 10.99% है।

मुख्य बिंदु-

- इस प्लांट का निर्माण 13,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा, इसे 2022 में कमीशन किया जायेगा।
- निर्माण पूरा होने पर इस प्लांट की नीम लेपित यूरिया की उत्पादन क्षमता 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी।
- उत्पादन के लिए कोयला व पेट कोल का उपयोग किया जायेगा। नीम लेपित यूरिया के कारण अन्य क्षेत्रों में यूरिया का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- इस प्लांट के लिए तलचर क्षेत्र में कोयला खदान को आबंटित किया गया है, ताकि प्लांट को आवश्यक कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

महत्त्व-

- इस प्लांट में कोयले से उत्पन्न गैस का उपयोग किया जायेगा, इससे यूरिया व गैस आयात के लिए भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी।
- इससे घरेलू कोयले का वैकल्पिक उपयोग भी संभव हो सकेगा।
- इस प्लांट द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को यूरिया व अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए रीसाइकिल किया जायेगा।

इज ऑफ लिविंग इंडेक्स

इंडियन एक्सप्रेस/बिजनेस लाइन/टाइम्स ऑफ इंडिया
(24 सितम्बर)

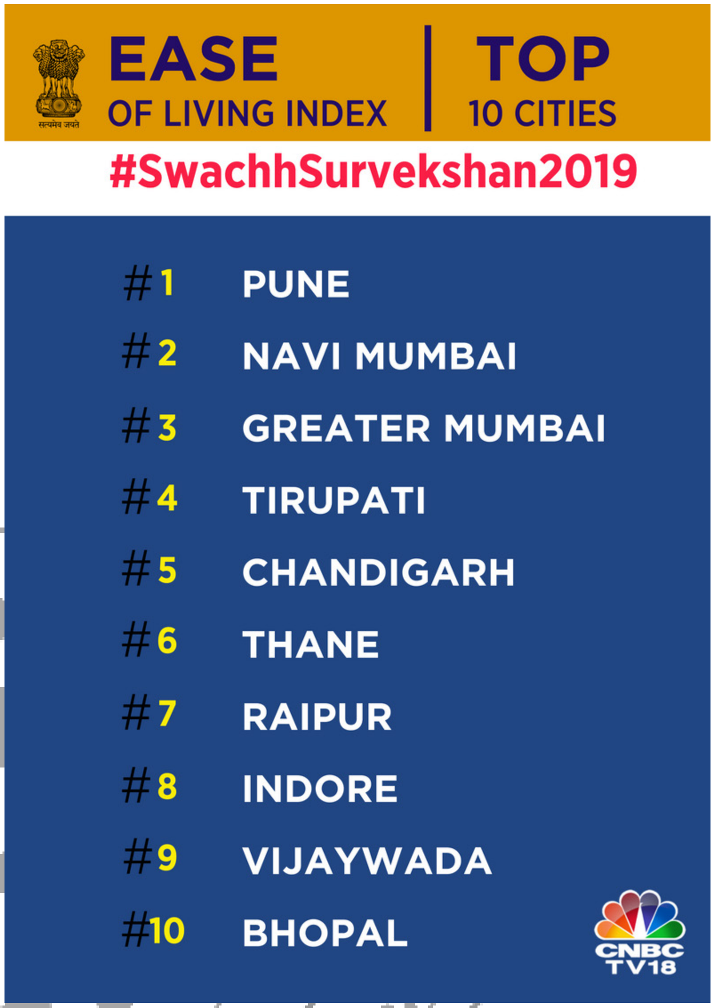

संदर्भ-

- हाल ही में भारत सरकार ने AMRUT (अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन) के अंतर्गत इज ऑफ लिविंग इंडेक्स (Ease of Living Index) अर्थात् जीवनयापन सूचकांक निर्गत किया है।
- इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश को शीर्षस्थ स्थान मिला है, जबकि ओडिशा और मध्यप्रदेश को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है।

क्या है?

- इस सूचकांक की संकल्पना शहरों के अंदर जीवन-यापन से सम्बंधित प्रमुख संकेतकों में हो रहे अच्छे कामों के आकलन के लिए की गई है।
- इस सूचकांक का पहला संस्करण जनवरी, 2018 में निर्गत हुआ था जिसमें भारत के 111 शहरों को रैंकिंग दी गई थी जिसमें पुणे को पहला स्थान मिला था।
- इस सूचकांक में वैसे 116 शहरों को रखा गया है जो स्मार्ट सिटी की प्रतिस्पर्द्धा में हैं, राजधानी नगर हैं एवं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है।

- इस सूचकांक के लिए शहरी स्थानीय निकायों से आँकड़ें जुटाए जाते हैं।
- ये संस्थागत (प्रशासन), सामाजिक (पहचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा), आर्थिक (अर्थव्यवस्था, रोजगार) जैसे चार मानदंडों पर आधारित है, जिसके आधार पर आंकड़े जमा किये जाते हैं।
- भौतिक कारक (अपशिष्ट जल और अपशिष्ट ठोस वस्तुओं का प्रबन्धन, प्रदूषण, आवास, समावेशिता, भूमि का मिश्रित उपयोग, बिजली, जल की आपूर्ति, परिवहन, सार्वजनिक खुले क्षेत्र)
- इन मानदंडों में संस्थागत एवं सामाजिक मानदंडों को 25-25 अंक हैं। जबकि भौतिक कारकों के लिए अधिकतम 45 अंक हैं। पाँच अंक आर्थिक कारकों के लिए हैं।

AMRUT क्या है?

- AMRUT पुरानी योजना जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण अभियान अर्थात् जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का एक नया अवतार है।
- इस मिशन के अंतर्गत शहरों में जन सुविधाओं से सम्बंधित आधारभूत संरचना का विकास सुनिश्चित किया जाता है।
- इन जन सुविधाओं में आने वाली सुविधाएँ हैं-जल की आपूर्ति, नालों का निर्माण, जल की निकासी, परिवहन और हरित क्षेत्रों और उद्यानों के विकास।

- 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए इस योजना के अन्दर केन्द्रीय सहायता 50% मिलती है और 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों के लिए केंद्र सरकार 1/3 राशि उपलब्ध कराती है।
- इस परियोजना के लिए राशि शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई जाती है।
- केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो राशि भेजती है उसे राज्य सरकार 7 दिनों के अन्दर सम्बंधित स्थानीय निकायों को उपलब्ध करा देती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट

हिंदुस्तान टाइम्स (25 सितम्बर)

संदर्भ-

- हाल ही में विश्व बैंक ने Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) द्वारा किये गये एक अध्ययन को प्रकाशित किया है।
- इस अध्ययन में यह बताया गया है कि कौन-कौन से देश शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर कितना खर्च कर रहे हैं।
- इसके लिए सरकारी एजेंसियों, विद्यालयों एवं स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्थाओं से आँकड़ें जुटाए गये थे।
- यह अपने ढंग का ऐसा पहला अध्ययन है जिसमें विभिन्न देशों की "मानव पूंजी" को मापने और उसकी तुलनात्मक स्थिति बताने की चेष्टा की गई है।
- अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जब किसी देश की मानव पूँजी में वृद्धि होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है।

भारत का स्थान

- शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश के मामले में भारत का विश्व में 158 वाँ स्थान है। भारत सूडान (157वाँ) से पीछे है और नामीबिया (159वाँ) से आगे है।
- दक्षिण-एशियाई देशों में भारत से नीचे स्थान पाने वाले देश हैं -पाकिस्तान (164वाँ), बांग्लादेश (161वाँ) और अफगानिस्तान (188वाँ)।
- दक्षिण-एशिया के वे देश जिनका प्रदर्शन भारत से अच्छा रहा, वे हैं-श्रीलंका (102वाँ), नेपाल (156वाँ), भूटान (133वाँ) और मालदीव (116वाँ)।
- 1990 में भारत का मानव पूँजी के मामले में 162वाँ स्थान था।

विश्व के अन्य देशों का प्रदर्शन

- रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड का स्थान सबसे ऊपर है।
- अमेरिका और चीन को क्रमशः 27वीं और 44वीं रैंकिंग मिली है।
- 1990 से लेकर 2016 के बीच जिस देश में सबसे अधिक मानव पूँजी बढ़ी है, वह तुर्की है।

Institute for Health Metrics and Evaluation

- एशिया के जिन देशों में पहले से उल्लेखनीय सुधार आया है, वे हैं -चीन, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम।
- लैटिन अमेरिका में सबसे अच्छा सुधार ब्राजील में देखा गया है।
- सहारा मरुभूमि के दक्षिण में स्थित देशों में मानव पूंजी की सबसे अधिक वृद्धि विषुवतीय देश गिनी में देखी गई।

* * *

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'चैपिंयस ऑफ अर्थ अवार्ड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. चैपिंयन ऑफ अर्थ अवॉर्ड को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (IPCC) प्रदान करता है।
   2. यह पुरस्कार केवल पर्यावरण हितैषी कार्य करने वाले सार्वजनिक व्यक्तियों को दिया जाता है।
   3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
   4. यंग चैपिंयस ऑफ अर्थ के तहत 15-30 वर्ष के व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?
   (a) 1 और 4 (b) 2, 3 और 4
   (c) 1, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

2. **कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सभी अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी गयी है।
   2. सभी प्रकार के मुद्दों का लाइव स्ट्रीमिंग किया जा सकेगा।
   3. लाइव स्ट्रीमिंग संबंधी नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये जाएंगे।
   4. संविधान के अनुच्छेद-135 के तहत लाइव स्ट्रीमिंग के नियम-कानून बनाये जायेंगे।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?
   (a) 1, 2 और 4 (b) 2, 3 और 4
   (c) 2 और 4 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. **कोयला गैसीफिकेशन उर्वरक प्लांट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. देश के पहले कोयला गैसीफिकेशन प्लांट का निर्माण झरिया (झारखण्ड) में किया जा रहा है।
   2. राष्ट्रीय केमिकल व फर्टीलाइजर्स लिमिटेड इस उर्वरक प्लांट का निर्माण करा रहा है।
   3. इस प्लांट द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों का उपयोगी तत्वों में रीसाइकिल किया जायेगा।
   4. इस संयंत्र द्वारा नीमलेपित यूरिया का उत्पादन किया जाएगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 4 (b) 1, 3 और 4
   (c) 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

4. **इज ऑफ लिविंग इंडेक्स (जीवन यापन सूचकांक) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. नीति आयोग द्वारा इज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है।
   2. नवीनतम सूचकांक में आन्ध्र प्रदेश को प्रथम एवं मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।
   3. इस सूचकांक में संस्थागत मानदण्डों को सबसे अधिक भारांश दिया गया है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

5. **विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित IHME के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**
   1. यह रिपोर्ट शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यक्तियों द्वारा किये गये खर्च से संबंधित है।
   2. बांग्लादेश, भूटान का प्रदर्शन भारत से अच्छा रहा।
   3. भारत का प्रदर्शन सूडान और नामीबिया से अच्छा है।
   4. मालदीव, श्रीलंका का प्रदर्शन भारत से अच्छा है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
   (a) 1 और 3 (b) केवल 3
   (c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

नोट- 26 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संबंधित प्रश्न) का व्याख्या सहित उत्तर-

1. (c) कथन 2, 3 व 4 सत्य है। रक्षामंत्री रक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है।
2. (c) कथन 4 सत्य है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड में कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक डिजिटल कक्षा का रूप दिया जायेगा। योजना का वित्तीयन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पाँस्बिलिटी से किया जायेगा। इस योजना में सफेद ब्लैक बोर्ड लगाये जायेंगे।
3. (a) कथन 1 व 3 सत्य है। ई-विधान का प्रयोग विधान सभाओं के अतिरिक्त सरकारी विभाग द्वारा किया जा सकता है।
4. (d) T×2 परियोजना को WWF द्वारा शुरू किया गया। इस योजना को 2010 में पीट्र्सबर्ग में व्याघ्र सम्मेलन में अपनाया गया। T×2 का लक्ष्य 2022 तक बाघों की संख्या दुगुनी करना है। नेपाल शीघ्र ही बाघों की संख्या दोगुनी करने वाला पहला राष्ट्र बनने वाला है।
5. (c) कथन 3 व 4 सत्य है। आधार को मोबाइल व बैंक से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु आवश्यक है।

* * *

GS World Committed To Excellence